

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 28 दिसम्बर, 2017

विषय:- सामुदायिक रेडियो स्टेशनों हेतु प्रोत्साहन नीति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सामुदायिक रेडियो का तात्पर्य एक ऐसी रेडियो सेवा से है, जिसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी हो और जो लोगों को उनकी भाषा में स्थानीय परिप्रेक्ष्य में वांछित जानकारियाँ उपलब्ध करवाये व स्थानीय समस्याओं के निदान में सहायता करे। सामुदायिक रेडियो जन-जागरूकता का एक सशक्त माध्यम हो सकता है और आपदा प्रबन्धन में जागरूकता के महत्व के दृष्टिगत इस माध्यम का उपयोग आपदा से पहले, आपदा के समय व आपदा के बाद सफलतापूर्वक किया जा सकता है।

प्रसारित किये जाने वाले कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी होने के कारण लोग सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं और इसी के कारण इनके माध्यम से प्रसारित की जा रही जानकारियों की लोगों में प्रायः अधिक स्वीकार्यता होती है। सामुदायिक रेडियो द्वारा समुदाय में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाने की क्षमता को स्वीकार करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिये लाईसेंस प्रदान करने की नीति को अत्यन्त सरल बनाया गया है ताकि शैक्षणिक संस्थानों, सिविल सोसाईटी और स्वैच्छिक संगठन के साथ-साथ अन्य गैर-लाभकारी संगठनों के द्वारा सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित कर के लोगों के मध्य विभिन्न जानकारियों का प्रचार-प्रसार किया जा सके।

उत्तराखण्ड राज्य अपनी स्थालाकृति, भूगर्भीय संरचना तथा अत्यधिक मौसमी वर्षा के कारण विभिन्न आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। विगत के अनुभव बताते हैं कि निरन्तरता में आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करने के लिये सभी के द्वारा आपदा सुरक्षा उपायों का स्वैच्छिक अनुपालन करना अत्यन्त आवश्यक है। ऐसे में सही जानकारियों को सही प्रारूप व भाषा में दूर-दराज क्षेत्रों तक पहुँच पाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। फिर यहाँ पहाड़ों में पहुँच से जुड़ी कठिनाईयों के कारण इन जानकारियों को हर जगह तक आसानी से पहुँचा पाना भी सरल नहीं है। ऐसे में सामुदायिक रेडियो, आपदा प्रबन्धन चक्र के सभी चरणों में आपदा रोकथाम, न्यूनीकरण, प्रतिवादन, संचार, सुरक्षित निर्माण, खोज एवं बचाव व अन्य से जुड़ी विभिन्न जानकारियों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिये एक सशक्त माध्यम के रूप में सामने आता है।

अतः उत्तराखण्ड राज्य में सामुदायिक रेडियो की गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ-साथ नये सामुदायिक रेडियो केन्द्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करने तथा पूर्व में स्थापित केन्द्रों को सुदृढ़ करने हेतु "सामुदायिक रेडियो स्टेशनों हेतु प्रोत्साहन नीति" को लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2 भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप सामुदायिक रेडियो केन्द्रों की स्थापना हेतु लाईसेंस प्राप्त संस्थान/सामुदायिक संस्थायें जो राज्य में सामुदायिक रेडियो केन्द्र स्थापित करना चाहते हैं या जिनके द्वारा राज्य में इस प्रकार के केन्द्र स्थापित किये गये हैं उन्हें उनके द्वारा दी जा रही सेवाओं को गुणवत्तापरक व प्रभावी बनाने के

साथ-साथ इन सेवाओं से राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों को आच्छादित करने के लिये आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा सहायता एवं आवश्यक सुविधायें निम्नानुसार उपलब्ध करवायी जायेगी:-

- 1.1 नये सामुदायिक रेडियो केन्द्र की स्थापना के लिये सम्बन्धित संस्थानों/सामुदायिक संस्थाओं को अधिकतम रु0 5.00 लाख की सीमा तक कुल परियोजना लागत की 30 प्रतिशत राशि एकमुश्त अनुदान के रूप में उपलब्ध करवायी जायेगी।
- 1.2 अनुदान प्राप्त करने के लिये सम्बन्धित संस्था को वांछित अभिलेखों के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा।
- 1.3 राज्य सरकार द्वारा दी जा रही इस सहायता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सामुदायिक रेडियो केन्द्रों के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से विशेष रूप में राज्य का सुदूरवर्ती क्षेत्र पूरी तरह से आच्छादित हो। अतः संसाधनों के सीमित होने की स्थिति में ऐसे जनपदों में सामुदायिक रेडियो केन्द्र स्थापित करने में इच्छुक संस्थानों/सामुदायिक संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी जो आपदा की दृष्टि से अधिक संवेदनशील हो और जहाँ पहले से सामुदायिक रेडियो केन्द्र संचालित नहीं हों।
- 1.4 किसी आपदा से प्रभावित होने के उपरान्त यथाशीघ्र पुनः प्रभावी रूप से सेवायें दे सकने के दृष्टिगत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त सामुदायिक रेडियो केन्द्र को अपने सभी संसाधनों का अनिवार्य रूप से आपदा बीमा करवाना होगा।
- 1.5 सरकार से सहायता प्राप्त करने से पूर्व सम्बन्धित संस्थान/संस्था द्वारा सुसंगत व विभाग द्वारा अनुमोदित तकनीकी संस्थान से यह पुष्टि करवानी होगी कि उनके द्वारा सामुदायिक रेडियो केन्द्र की स्थापना हेतु चयनित स्थान भू-वैज्ञानिक दृष्टि से सुरक्षित है व इस हेतु बनाये जा रहे या बनाये गये भवन के निर्माण में भूकम्प सुरक्षित निर्माण तकनीक का उपयोग न होने की स्थिति में सम्बन्धित भवन का भूकम्पीय सुदृढीकरण करवाने के उपरान्त उक्त का प्रमाण-पत्र सम्बन्धित संस्थान से प्राप्त कर विभाग को उपलब्ध करवाना होगा।
- 1.6 राज्य सरकार से सहायता प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित संस्थान/संस्था को स्थानीय स्तर पर न्यूनतम 03 वर्षों तक कार्य करने का अनुभव अनिवार्य होगा अथवा इस अवधि से स्थानीय स्तर पर कार्यरत संस्था के सहयोग से रेडियो स्टेशन स्थापित किया जाना होगा।
- 1.7 राज्य में स्थापित सामुदायिक रेडियो केन्द्रों को आर्थिक स्वावलम्बन प्रदान करने तथा इनकी गतिविधियों में निरन्तरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा राज्य सरकार के साथ-साथ केन्द्र सरकार के विभागों से समन्वय कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रचार-प्रचार हेतु उपलब्ध बजट के एक नियत अंश का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर जनपद स्तर पर स्थापित सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को विज्ञापन देने के लिये किया जाये। इस प्रकार के विज्ञापनों के लिये राज्य सरकार के सूचना व जन-सम्पर्क विभाग द्वारा अनुमन्य दरें मान्य होंगी।
- 1.8 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों द्वारा आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित जानकारियों को जन मानस तक पहुँचाने के लिये जनपद व राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को सहयोग दिया जायेगा व